अभियोजन स्वीकृति हेतु भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा दिनांक 31–10–2022 तक भिजवाये गए लम्बित अभियोगों को विभागवार संख्या

क्र.स.	विभाग का नाम	लम्बित प्रकरण
1	कार्मिक विभाग	64
2	कार्मिक विभाग–केन्द्रीय	2
3	राजस्व	44
4	पंचायत	115
5	पुलिस	23
6	अन्य राज्य पुलिस	2
7	कृषि	8
8	जल संसाधन व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	12
9	जल ग्रहरण विभाग एवं भू संरक्षण	1
10	चिकित्सा	32
11	नगरीय विकास विभाग	15
12	स्वायत शासन	59
13	ऊर्जा	14
14	आबकारी विभाग	12
15	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1
16	महिला एवं बाल विकास विभाग	10
17	पशुपालन	3
18	अनुसुचित जाति एवं जन जाति विकास निगम	1
19	महालेखा	3
20	वित्त विभाग	2
21	कोष एवं लेखा	6
22	सहकारिता विभाग	7
23	शिक्षा	14
24	विश्वविद्यालय	3
25	सार्वजनिक निर्माण विभाग	8
26	विधि	1
27	परिवहन	13
28	श्रम विभाग एवं श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता	2
29	राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद	1
30	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	2
31	खनिज	9
32	गृह रक्षा दल	1
33	वन विभाग	8
34	उद्योग विभाग	1
35	सूचना एवं प्राद्यौगिक	3
36	कारागृह	2
37	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	4

38	निर्वाचन आयोग	1
39	श्रम एवं नियोजन विभाग–केन्द्रीय	4
40	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	1
41	एमएनआईटी	1
42	रेल	6
43	बैंक	5
44	नारकोटिक्स	1
45	सीजीएसटी	3
46	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड	1
47	आर्मी	1
48	एक्स सर्विसमेन	2
49	बीवीजी	1
50	आयकर विभाग	1
51	एनपीसीसी	1
52	रीडकोर	1
	योग	538

कार्मिक विभाग में लम्बित	विभागाध्यक्षों के पास लम्बित	कुल लम्बित
64+2 = 66	472	538